मास्टर प्लान में शामिल होंगे टीओडी जोन और पीआरटी के अलाइनमेंट

शहरों के मोबिलिटी प्लान और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरकनेक्ट होंगे

राज्य ब्यूरो, जागरण ● देहरादून: उत्तराखंड के जिलों को आगामी 50 वर्षों तक जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए कंप्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान (सीएमपी) को नए सिरे से लागू करने की तैयारी शुरू की गई है। यह योजना एक शहर तक सीमित नहीं रहकर पूरे राज्य को कवर करेगी, जिसमें सभी शहरों के मोबिलिटी प्लान, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क व रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को इंटरकनेक्ट किया जाएगा, ताकि जाम व यातायात की मुश्किलों से जूझ रहे उत्तराखंड को राहत मिल सके। मास्टर प्लान में भी इसका प्रविधान होगा। जाम से बचने के लिए आवास विभाग तीन प्रमुख कदम उठाने जा रहा है।

कंप्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान (व्यापक गतिशीलता योजना): इस प्लान में सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग प्रोत्साहित कर जाम को कम कर यात्रा को सुरक्षित व आसान बनाया जाएगा। ट्रैफिक और परिवहन का सर्वे व डेटा विश्लेषण कर सड़क नेटवर्क में सुधार और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मजबूत किया जाएगा। पैदल-साइकिल ट्रैक, पार्किंग मैनेजमेंट, रोड सेफ्टी के साथ प्रदूषण घटाने के उपायों व भविष्य की ट्रैफिक जरूरतों के अनुसार योजना तैयार की जाएगी।

सचिवालय में कंप्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान लागू करने को लेकर हुई बैठक ● जागरण

मास्टर प्लान में शामिल होगा रूट

पर्सनल रैपिड ट्रांजिट जैसे मेट्रो, पाड टैक्सी या अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अलाइनमेंट (रूट) को मास्टर प्लान में शामिल किया जाएगा, ताकि भविष्य में इन परियोजनाओं को धरातल पर उतारने में कोई समस्या न आए। देहरादून व हरिद्वार के मास्टर प्लान में इन अलाइमेंट को शामिल कर लिया गया है, अन्य शहरों में भी जल्द किया जाएगा।

73 किलोमीटर लंबा बनेगा ई-बीआरटीएस

आवास सचिव डा. आर राजेश कुमार ने बताया कि कंप्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान के तहत देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच 73 किलोमीटर लंबा ई-बीआरटीएस (इलेक्ट्रिक बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम) बनाया जाएगा, जिससे तीनों शहरों के बीच आवागमन सुविधाजनक होगा। वहीं हरिद्वार में पर्सनल रैपिड ट्रांजिट (पीआरटी) सिस्टम लागू करने का प्रस्ताव है, जो धार्मिक पर्यटन को नई दिशा देगा।

ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (परिवहन उन्मुख विकास): इसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्थलों के आसपास शहरी विकास किया जाएगा, ताकि सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग आसानी से किया जा सके। प्रत्येक शहर में टीओडी स्पाट विकसित किए जाएंगे।